पीके टाइम्स

दैनिक
जनता की आवाज...
लोक टुडे
विश्वसनीय खबरों का सर्वश्रेष्ठ अखबार

pktimesnews.com
loktodaynews.com
PK Times News
thepktimesofficial
pk_timesofficial

वर्ष: 12 अंक: 340 | मूल्य: 1.00 रुपए | पृष्ठ: 4 | गुरुवार 25 जून 2026 | RNI No. RAJHIN/2013/50649

एचआरआरएल प्रबंधन ने रिफाइनरी से निकल रहे विभिन्न प्रोडक्ट्स के सैम्पल किए भेंट

पचपदरा रिफाइनरी राजस्थान का 'ग्रोथ इंजन', पीएम मोदी 4 जुलाई को करेंगे उद्घाटन

सीएम ने पचपदरा रिफाइनरी को लेकर सचिवालय में ली एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक

लोक टुडे। जयपुर

जयपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 4 जुलाई को बालोतरा के पचपदरा आएंगे। इस अवसर पर पचपदरा रिफाइनरी के उद्घाटन एवं जयपुर मेट्रो फेज-2 के शिलान्यास के साथ ही प्रधानमंत्री प्रदेशभर में विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण एवं शिलान्यास की सौगात देंगे। इस दौरान विभिन्न सरकारी नौकरियों में चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर प्रधानमंत्री की इस प्रस्तावित यात्रा की तैयारियों को लेकर बैठक ली और ऐतिहासिक आयोजन को लेकर निर्देश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी सेवा में नियुक्ति पत्र प्राप्त करना प्रत्येक युवा के जीवन का गौरवपूर्ण क्षण होता है। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी जिलों में विशेष आयोजन के साथ नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले युवाओं एवं आमजन को प्रधानमंत्री के मुख्य कार्यक्रम से वर्चुअल माध्यम से जोड़ा जाए, ताकि वे इस ऐतिहासिक अवसर के सहभागी बन सकें। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत से लेकर जिला स्तर तक आयोजित कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं, जनप्रतिनिधियों एवं आमजन की सहभागिता सुनिश्चित की जाए ताकि यह आयोजन विकास, रोजगार एवं सहभागिता का उत्सव बन सकें।

सीएम की निगरानी से दूर हुई अड़चनें

बैठक के दौरान एचआरआरएल प्रबंधन ने मुख्यमंत्री को प्रोजेक्ट की वर्तमान प्रगति से अवगत कराया। प्रबंधन ने खुलकर स्वीकार किया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा की जा रही निरंतर और सूक्ष्म समीक्षा (माइक्रो मॉनिटरिंग) की बदौलत ही कार्य की रफ्तार दोगुनी हुई है। प्रशासनिक और तकनीकी स्तर पर लंबे समय से लंबित पड़ी अड़चनों को सरकार ने तुरंत दूर किया, जिससे यह प्रोजेक्ट अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है।

ऐतिहासिक आयोजन के साथ विकास, रोजगार और सहभागिता का बनें उत्सव- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

आधा दर्जन से अधिक यूनिट्स एक्टिव, प्रोडक्ट्स तैयार

रिफाइनरी परिसर से बड़ी कामयाबी यह सामने आई है कि यहां आधा दर्जन से अधिक प्रमुख औद्योगिक इकाइयां (यूनिट्स) पूरी तरह चालू हो चुकी हैं। इन क्रियाशील यूनिट्स में न केवल कच्चे तेल की प्रोसेसिंग सुचारू रूप से चल रही है, बल्कि कई उच्च गुणवत्ता वाले पेट्रोकेमिकल उत्पादों का कमर्शियल प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया गया है। यह राजस्थान को देश के बड़े पेट्रोकेमिकल हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में मील का पत्थर है।

पश्चिमी राजस्थान की बदलेगी तकदीर

मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि यह रिफाइनरी केवल एक औद्योगिक ढांचा नहीं, बल्कि राजस्थान के राजस्व और विकास को नई ऊंचाई देने वाला माध्यम है। इसके पूर्ण रूप से शुरू होने पर मारवाड़ सहित पूरे पश्चिमी राजस्थान में औद्योगिक निवेश की बाढ़ आएगी। स्थानीय युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाखों नए रोजगार पैदा होंगे।

युद्धस्तर पर तैयारी, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन -

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को बचे हुए निर्माण कार्यों और तकनीकी फिनिशिंग को युद्धस्तर पर पूरा करने के कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस ऐतिहासिक और राष्ट्र-महत्व के प्रोजेक्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर-कमलों द्वारा किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार और एचआरआरएल का शीर्ष प्रबंधन उद्घाटन समारोह की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गया है।

गहलोत ने फिर दोहराया विवादित बयान, बीजेपी पर बोला तीखा हमला

'करोड़ों में बिक रहे विधायक-सांसद, उन्हें घोड़ा-गधा नहीं कहूं तो क्या कहूं' : गहलोत

जोधपुर।

राजस्थान की सियासत में दल-बदल और जनप्रतिनिधियों की खरीद-फरोख्त को लेकर छिड़ी बहस के बीच पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने विवादित बयान को एक बार फिर दोहराते हुए भाजपा पर तीखा हमला बोला है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ द्वारा उनके बयान को लोकतंत्र का अपमान बताए जाने के बाद गहलोत ने पलटवार करते हुए कहा कि जो जनप्रतिनिधि करोड़ों रुपये में बिक जाते हैं, उन्हें वह 'घोड़ा-गधा, भैंस-बकरी' नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे।

'करोड़ों में बिक रहे विधायक-सांसद, उन्हें घोड़ा-गधा नहीं कहूं तो क्या कहूं' : गहलोत

गहलोत ने कहा कि देश में लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा जनप्रतिनिधियों की खरीद-फरोख्त से पैदा हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में विधायक और सांसद करोड़ों रुपये में बिक रहे हैं। जनता जिन लोगों को अपने विश्वास के साथ चुनकर विधानसभा और संसद में भेजती है, वही यदि सत्ता और पैसे के लालच में अपना राजनीतिक जमीर बेच दें तो यह लोकतंत्र के साथ विश्वासघात है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, 'देश में 5 करोड़, 10 करोड़ और 50 करोड़ रुपये तक में विधायक और सांसद बिक रहे हैं। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि यदि इस तरह बाजार में बिकने लगें तो उन्हें घोड़ा-गधा, भैंस-बकरी नहीं कहूं तो क्या कहूं? मैं उनकी पूजा तो नहीं कर सकता।' गहलोत ने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वे अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि असली सवाल उनके शब्द नहीं, बल्कि लोकतंत्र में हो रही खरीद-फरोख्त है, जिस पर भाजपा जवाब देने से बच रही है।

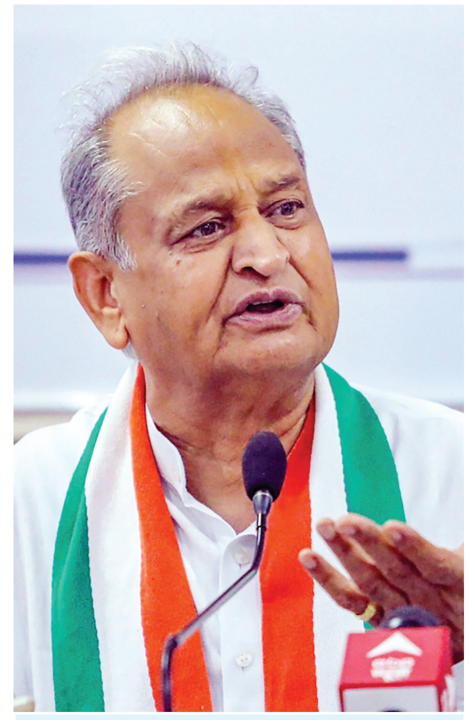

मदन राठौड़ की आलोचना पर गहलोत का पलटवार, बोले- लोकतंत्र का असली अपमान खरीद-फरोख्त

गहलोत के इस बयान के बाद राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर सियासी तापमान बढ़ गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने जहां इसे जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का अपमान बता रही है, वहीं कांग्रेस इसे लोकतंत्र की रक्षा और राजनीतिक खरीद-फरोख्त के खिलाफ उठाई गई आवाज करार दे रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में यह मुद्दा प्रदेश की राजनीति में और अधिक गरमाने के संकेत दे रहा है।

कोलकाता में 'मौत' का ढलाईघर: निर्माणाधीन गोदाम का शेड गिरा, 5 की मौत

तारातला में कंक्रीट ढलाई के दौरान भरभराकर ढहा भारी स्ट्रक्चर; मलबे से आ रही चीखों के बीच सेना

एनडीआरएफ और पुलिस का महा-रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, 50-55 लोगों के दबे होने की आशंका

लोक टुडे। कोलकाता

पश्चिम कोलकाता का तारातला इलाका बुधवार दोपहर अचानक चीख-पुकार और धूल के गुबार से ढंक गया। ट्रांसपोर्ट डिपो रोड पर ब्रेस ब्रिज के पास बन रहे एक निजी गोदाम की छत (शेड) दोपहर करीब 12:30 से 1 बजे के बीच ताश के पत्तों की तरह ढह गई। जिस वक्त यह हादसा हुआ, वहां करीब 50 से 60 मजदूर कंक्रीट ढलाई और वेल्डिंग के काम में लगे थे। भारी-भरकम लोहे के बीम और कंक्रीट का स्लैब सीधे काम कर रहे मजदूरों पर आ गिरा। हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एक मजदूर के सिर पर लोहे का पोल गिरने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार अन्य ने मलबे के भीतर ही दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी मिलते ही सबसे पहले स्थानीय लोग और पुलिस बचाव के लिए दौड़े। बाद में मलबे की सघनता को देखते हुए सेना और एनडीआरएफ को मोर्चे पर बुलाया गया। मलबे से अब तक 13 घायलों को निकालकर एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से कई की हालत नाजुक है।

इनसाइड स्टोरी : लापरवाही की नींव पर खड़ी थी 'मौत की छत'

मौके पर मौजूद चश्मदीदों के अनुसार इस हादसे के पीछे कई गंभीर लापरवाही और तकनीकी खामियां सामने आ रही हैं।

1. वेल्डिंग की चिंगारी और कमजोर स्ट्रक्चर

प्राथमिक जांच और स्थानीय सूत्रों के अनुसार, हादसे के ठीक पहले गोदाम के भीतर लोहे के बड़े फ्रेम पर वेल्डिंग का काम चल रहा था। उसी समय ऊपर कंक्रीट की भारी ढलाई भी की जा रही थी। लोहे का अस्थायी ढांचा कंक्रीट के अत्यधिक वजन को संभाल नहीं सका और वेल्डिंग पॉइंट के कमजोर होने या वहां किसी तकनीकी गड़बड़ी के कारण पूरा का पूरा शेड एक झटके में नीचे आ गया।

2. बारिश ने खोली निर्माण सामग्री की पोल

स्थानीय निवासियों का दावा है कि मंगलवार को इलाके में हुई भारी बारिश की वजह से निर्माण स्थल की मिट्टी और कुछ कच्चा स्ट्रक्चर कमजोर हो गया था। इसके बावजूद बिल्डर और ठेकेदार ने सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर बिना किसी सुरक्षा ऑडिट के बुधवार को भारी ढलाई का काम शुरू करवा दिया।

3. नियमों को ताक पर रखकर अवैध निर्माण की आशंका

घटनास्थल पर पहुंचे राजनीतिक नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच इस बात को लेकर तीखी बहस छिड़ गई है कि क्या इस विशाल गोदाम के निर्माण की वैध अनुमति थी? भाजपा नेता राकेश सिंह और शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने मौके का मुआयना किया। विपक्ष का आरोप है कि इलाके में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माणों को बढ़ावा दिया जा रहा था। हालांकि, खेल मंत्री इंद्रनील खान ने कहा, 'यह राजनीति का समय नहीं है, हमारी पहली प्राथमिकता मलबे में दबे इंसानों को जिंदा बाहर निकालना है।'

4. ओडिशा के व्यवसायी की जमीन, प्राइवेट फर्म को लीज

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, जिस जमीन पर यह गोदाम बन रहा था, वह ओडिशा के एक बड़े व्यवसायी की है। उन्होंने इसे एक निजी लॉजिस्टिक्स फर्म को लीज पर दिया था। कोलकाता नगर निगम और पुलिस ने अब गोदाम मालिक और निर्माण कंपनी के खिलाफ जांच शुरू कर दी है और दोषियों से पूछताछ की तैयारी की जा रही है।

ग्राउंड रिपोर्ट : मलबे के नीचे से 'बचा लो' की पुकार, गैस कटर और वर्टिकल ड्रिलिंग से रास्ता बना रही सेना

तारातला के दुर्घटनास्थल पर इस समय युद्ध जैसी स्थिति है। मलबे के नीचे दबे मजदूरों की रोने और मदद मांगने की आवाजें साफ सुनी जा सकती हैं। कंक्रीट के बड़े स्लैब और उलझे हुए लोहे के भारी गर्डर्स के कारण बचाव दल को अंदर घुसने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

गैस कटर का इस्तेमाल: सेना और आपदा प्रबंधन के जवान गैस कटर के जरिए लोहे के विशाल बीम को काटकर रास्ता बना रहे हैं।

वर्टिकल ड्रिलिंग: मलबे के नीचे हवा और रोशनी पहुंचाने तथा फंसे हुए लोगों तक पहुंचने के लिए ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग (सीधी खुदाई) की जा रही है।

भारी क्रेनें तैनात: मलबे और लोहे के गर्डर्स को हटाने के लिए कई भारी-भरकम हाइड्रोलिक क्रेनें मौके पर काम कर रही हैं।

सांत्वना देता रेस्क्यू दल: मलबे के पास तैनात एक पुलिस अधिकारी ने बताया, 'हम नीचे से आ रही आवाजों का पीछा कर रहे हैं। हम लगातार नीचे फंसे लोगों से बात कर रहे हैं और उन्हें ढांढस बंधा रहे हैं कि घबराएं नहीं, हम जल्द उन तक पहुंच रहे हैं।'

सरकार का बड़ा एक्शन: विधायक निधि की नई गाइडलाइन, मांग होने पर ही अनुशंसा कर सकेंगे माननीय

जयपुर

विधायक निधि में भ्रष्टाचार पर खुलासे पर सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमएलए लेड) में खर्च को पारदर्शी बनाने के लिए गाइडलाइन में 6 संशोधन किए हैं। इनके लागू होने के बाद विधायक बिना मांग के विकास कार्यों की अनुशंसा नहीं कर पाएंगे। अनुशंसा पत्र में विधायक कार्यकारी एजेंसी का नाम भी नहीं लिखेंगे, कलेक्टर और जिला परिषद के सीईओ इसे तय करेंगे।

अनुशंसा के बाद संबंधित विभाग यह पता करेगा कि कार्य फिजिबल है या नहीं? प्रशासनिक स्वीकृति से पहले यह भी देखा जाएगा कि जिस कार्य की अनुशंसा की है वो बजट घोषणा और सरकार की किसी योजना में तो नहीं होना है। निधि का ज्यादातर हिस्सा विकास कार्यों पर खर्च होगा, सीधी खरीद सीमित मात्रा में होगी। एक साल के लिए निर्धारित 5 करोड़ की राशि उसी वित्तीय वर्ष में खर्च करनी होगी, बजट कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। अनुशंसा से कार्य होने तक की पूरी प्रक्रिया का विभाग की वेबसाइट पर लाइव अपडेट भी किया जाएगा।

सावंत कमेटी ने की संशोधन की सिफारिश

सरकार ने 15 दिसंबर को तीनों विधायकों की विधायक निधि सीज कर दी और जांच के लिए मुख्य सतर्कता आयुक्त व गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव भास्कर सावंत की अध्यक्षता में समिति बनाई। इसने अपनी रिपोर्ट में गाइडलाइन में बदलाव करने की सिफारिश की थी। इनके आधार पर ही ग्रामीण विकास विभाग ने इसका खाका तैयार किया है।

राजस्थान टाउनशिप नीति में बड़ा बदलाव; अवैध कॉलोनियों पर कसेगा शिकंजा, नक्शे पास कराना हुआ आसान

विभिन्न विभागों और स्टेकहोल्डर्स से मिले सुझावों के बाद नियम हुए और अधिक स्पष्ट; नियोजित विकास को मिलेगी रफ्तार

मनोहरसिंह खोखर। जयपुर

राजधानी सहित प्रदेशभर के शहरों में नियोजित शहरी विकास और सुविधायुक्त कॉलोनियों के निर्माण के लिए लागू की गई 'राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी-2024' के क्रियान्वयन को लेकर राज्य सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग ने बुधवार को एक नया स्पष्टीकरण आदेश जारी कर इस नीति के व्यावहारिक क्रियान्वयन में आ रही तकनीकी और व्यावहारिक अड़चनों को दूर कर दिया है। विभागीय सूत्रों के अनुसार, नीति के लागू होने के बाद से ही विभिन्न स्टेकहोल्डर्स, क्रेडाई जैसे बिल्डर्स संगठनों और स्थानीय निकायों से कुछ नियमों को लेकर व्यावहारिक कठिनाइयां सामने आ रही थीं। इसी के परिप्रेक्ष्य में आमजन और रियल एस्टेट सेक्टर को राहत देने के लिए नियमों को और अधिक सरल व स्पष्ट किया गया है।

क्यों पड़ी स्पष्टीकरण की जरूरत?

राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी-2024 के तहत राज्य में अवैध और अव्यवस्थित कॉलोनियों पर लगाम लगाने के लिए कड़े नियम बनाए गए हैं। हालांकि, विकास कार्यों की जिम्मेदारी, भूखंडों के प्रतिशत विभाजन और सुरक्षा गारंटी जैसी शर्तों को लेकर धरातल पर भ्रम की स्थिति बनी हुई थी। जारी स्पष्टीकरण में खासकर इन बिंदुओं को साफ किया गया है। इनमें 5000 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल के एकल पट्टा प्रकरणों में सुविधा क्षेत्र के नियमों और उसके बदले ली जाने वाली समतुल्य राशि के प्रावधानों को पूरी तरह स्पष्ट किया गया है। नीति के अनुसार टाउनशिप का पूर्णता प्रमाण पत्र मिलने के बाद 5 साल तक या रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के गठन तक रखरखाव की जिम्मेदारी डेवलपर की होती है। इसके लिए डेवलपर का 2.5% भूखंड प्राधिकरण के पास रहन (गिरवी) रखने के तकनीकी नियमों को और व्यावहारिक बनाया गया है। इसके अलावा कॉलोनियों में 7% क्षेत्र पार्क/खेल मैदान और 8' सार्वजनिक उपयोगिता (जैसे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट या स्कूल-अस्पताल जैसी सुविधाएं) के लिए छोड़ने की अनिवार्य शर्तों को स्थानीय निकायों के स्तर पर लागू करने की प्रक्रिया को सरल किया गया है।

अवैध कॉलोनियों पर लगेगी लगाम

यूडीएच विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस स्पष्टीकरण के बाद निकायों में लंबित पड़े टाउनशिप योजनाओं के ले-आउट प्लान और स्वीकृतियों के मामलों का तेजी से निस्तारण हो सकेगा। इससे न केवल रियल एस्टेट सेक्टर में मंदी का दौर खत्म होगा, बल्कि मकान या भूखंड खरीदने वाले आम उपभोक्ताओं को भी बुनियादी सुविधाओं की गारंटी मिलेगी। नीति में पर्यावरण संरक्षण के तहत वर्षा जल संचयन और अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण जैसी शर्तों को भी अनिवार्य रखा गया है, जिसे अब स्पष्ट दिशानिर्देशों के साथ लागू किया जाएगा।

राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी-2024 की मूल बातें?

न्यूनतम क्षेत्र: राज्य में किसी भी नई आवासीय योजना के लिए न्यूनतम क्षेत्र 5000 वर्ग मीटर होना आवश्यक है। **बिक्री योग्य क्षेत्र:** कुल भूमि का अधिकतम 60% हिस्सा ही बेचा जा सकता है। **पार्क व खेल मैदान:** सभी क्षेत्रफल की योजनाओं में 7% हिस्सा पार्क और खेल के मैदान के लिए आरक्षित रहेगा। **सुविधा क्षेत्र:** 8% भूमि सामुदायिक केंद्र, स्कूल, अस्पताल या सार्वजनिक उपयोगिता के लिए छोड़नी होगी। **कमजोर वर्ग को राहत:** ईडब्ल्यूएस र एलआईजी श्रेणी के लिए आरक्षित भूखंडों का आवंटन अब स्थानीय निकाय (नगर निगम/नगर पालिका) करेंगे।

अब स्पष्टीकरण से किसे क्या फायदा?

आम जनता को: भ्रम दूर होने से स्वीकृत योजनाओं में भूखंड खरीदना सुरक्षित होगा, मूलभूत सुविधाएं समय पर मिलेंगी। **बिल्डर्स/डेवलपर्स को:** नियमों के सरलीकरण से विभिन्न स्थानीय निकायों (जैसे JDA, नगरीय सुधार न्यास) से कॉलोनियों के नक्शे और ले-आउट जल्दी पास हो सकेंगे। **सरकर को:** रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता आएगी और अनियोजित कॉलोनियों के विकास पर रोक लगेगी।

संपादकीय

आस्था के आंगन में अमानत में खयानत और व्यवस्था की ढिलाई

अयोध्या के भव्य राम मंदिर में देश-दुनिया के कोने-कोने से आने वाले श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। हर आंख में श्रद्धा के आंसू हैं और हर दिल में रामलला के प्रति अगाध समर्पण। इस समर्पण का एक रूप उस चढ़ावे और दान में भी दिखता है, जिसे श्रद्धालु अपनी गाढ़ी कमाई से निकालकर प्रभु के चरणों में अर्पित करते हैं। लेकिन इसी आस्था के सबसे बड़े केंद्र से जब चढ़ावा चोरी होने की खबरें सामने आती हैं, तो वह सिर्फ एक आर्थिक अपराध नहीं रह जाती, बल्कि करोड़ों सनातनी आस्थावानों के विश्वास पर वज्रपात जैसी होती है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही विशेष जांच दल (एसआईटी) की शुरुआती पड़ताल ने जो खुलासे किए हैं, वे हैरान करने वाले भी हैं और व्यवस्था की गंभीर खामियों को उजागर करने वाले भी। एसआईटी की जांच में सबसे चिंताजनक बात यह सामने आई है कि इस पूरे प्रकरण में हर कदम पर लापरवाही, अनदेखी और सुरक्षा मानकों की धज्जियां उड़ाई गईं। जांच रिपोर्ट साफ इशारा करती है कि यह कोई अचानक हुई छोटी-मोटी चोरी नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित और ढीली व्यवस्था का फायदा उठाकर अंजाम दी गई वारदात थी। इस मामले में न केवल राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के स्तर पर प्रशासनिक अनदेखी और ढिलाई साबित हो रही है, बल्कि दान राशि की गणना (काउंटिंग) की जिम्मेदारी संभाल रहे देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के कर्मियों की संलिप्तता या घोर लापरवाही भी प्रमाणित हो रही है। जब रक्षक ही भक्षक की भूमिका में आ जाएं या अपनी आंखें मूंद लें, तो व्यवस्था का ढहना तय हो जाता है। कहानी का सबसे कड़वा और अजीब पहलू इसके बाद शुरू होता है। किसी भी निष्पक्ष जांच और पारदर्शी प्रक्रिया का पहला नियम यह होता है कि जिन लोगों पर उंगली उठे, उन्हें तुरंत प्रभाव से उस जिम्मेदारी से दूर कर दिया जाए। लेकिन राम मंदिर के काउंटिंग रूम में एक अलग ही कहानी चल रही है। एसआईटी की ओर से सवाल उठाए जाने और लापरवाही प्रमाणित होने के बावजूद, आज भी उन्हीं बैंककर्मियों से चढ़ावे की गणना कराई जा रही है, जो संदेह के घेरे में हैं। एसबीआई प्रबंधन द्वारा अपने स्टाफ को न बदला जाना न केवल प्रशासनिक सिद्धांतों के खिलाफ है, बल्कि इससे आम जनता और श्रद्धालुओं के बीच तरह-तरह की चर्चाएं और कयासबाजियां तेज हो गई हैं। लोग यह पूछने पर मजबूर हैं कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि दागी और संदिग्ध चेहरों को ही दोबारा नोटों की गड्डियां थमा दी गई हैं? लापरवाही का यह सिलसिला सिर्फ बैंक स्टाफ तक ही सीमित नहीं है। बैंक के स्तर से उस निजी सुरक्षा या कैश हैंडलिंग एजेंसी को भी नहीं बदला गया, जिसके कंधों पर मंदिर के दानपात्रों से नकदी एकत्रित करके उसे सुरक्षित रूप से गणना कक्ष (काउंटिंग रूम) तक ले जाने का संवेदनशील दायित्व है। सूत्रों की मानें तो इस पूरी प्रक्रिया में लगे हुए सभी पुराने कर्मी आज भी पूर्व की भांति अपनी ड्यूटी पर सीना ताने तैनात हैं। यह स्थिति तब है जब जांच एजेंसियां मान चुकी हैं कि कड़ियों को जोड़ने वाली इस चेन में ही कहीं न कहीं खोट था। इस पूरे घटनाक्रम में राहत और कड़ाई की एकमात्र किरण राम मंदिर ट्रस्ट के रुख में दिखाई देती है। प्रशासनिक अनदेखी के आरोपों का सामना कर रहे ट्रस्ट ने देर से ही सही, लेकिन अपने स्तर पर कुछ सुधारात्मक कदम उठाए हैं। ट्रस्ट ने आंतरिक कार्रवाई करते हुए अपने उन सभी संदिग्ध कर्मियों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है, जिनकी भूमिका पर जरा सा भी संदेह था। इसके साथ ही, दान राशि को सुरक्षित रखने और गणना प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी व अभेद्य बनाने के लिए एक पूर्व सैन्य अधिकारी की तैनाती की गई है। अब पूरी गणना प्रक्रिया और नकदी का प्रबंधन इस पूर्व सैन्य अधिकारी की सख्त निगरानी में संपन्न कराया जा रहा है, जिससे कम से कम ट्रस्ट के स्तर पर सुरक्षा को लेकर एक अनुशासन दिखाई दे रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि जब ट्रस्ट कड़े कदम उठा सकता है, तो एसबीआई जैसा प्रतिष्ठित संस्थान इतनी सुस्ती और ढिलाई क्यों बरत रहा है? क्या बैंक अधिकारियों को करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं और आस्था के प्रतीक इस मंदिर की साख की चिंता नहीं है? बैंक और संबंधित एजेंसी का यह अड़ियल या उदासीन रवैया न केवल एसआईटी की जांच को प्रभावित कर सकता है, बल्कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ की आशंका को भी जन्म देता है। राम मंदिर सिर्फ पत्थरों और नक्काशी से बना एक ढांचा नहीं है, यह भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना का जीवंत प्रतीक है। यहां आने वाला एक-एक पैसा पवित्र है, जो किसी गरीब की मन्नत या किसी अमीर के समर्पण का हिस्सा है। इस पैसे की सुरक्षा और इसका सही प्रबंधन उतनी ही पवित्रता से होना चाहिए, जितनी पवित्रता से रामलला की पूजा की जाती है। एसआईटी को मिली खामियां यह चेतावनी हैं कि आधुनिक तकनीक, सीसीटीवी कैमरों और सुरक्षा घेरे के बावजूद, यदि मानवीय नीयत में खोट हो और प्रशासनिक निगरानी कमजोर हो, तो कोई भी किला सुरक्षित नहीं है। अब समय आ गया है कि इस पूरे मामले में उच्च स्तर से हस्तक्षेप हो। एसबीआई और संबंधित नकदी प्रबंधन एजेंसी को तुरंत प्रभाव से अपने पूरे स्टाफ को बदलकर एक नई, निष्पक्ष और बेदाग टीम को इस कार्य में लगाना चाहिए। इसके साथ ही, ट्रस्ट और बैंक के बीच समन्वय को और मजबूत करते हुए एक ऐसी फुल-प्रूफ व्यवस्था बनानी होगी, जहां इंसानी दखल कम से कम हो और तकनीक के जरिए पारदर्शिता अधिकतम हो। आस्था के इस पावन आंगन को किसी भी तरह के भ्रष्टाचार या लापरवाही के ग्रहण से बचाना बेहद जरूरी है, क्योंकि यहां हो रही हर चूक सीधे करोड़ों रामभक्तों के विश्वास पर चोट करती है।

मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं... लेकिन आज लखनऊ मुस्कुरा नहीं पा रहा

वीरेश तरार

लखनऊ आज दुःखी है। शर्मिंदा भी है। लेकिन यदि यह पीड़ा समाज को जागरूक कर सके, यदि यह 15 युवाओं की असमय मृत्यु को एक बड़े सामाजिक परिवर्तन का कारण बना सके, तो शायद भविष्य में किसी और शहर को ऐसी शर्मिंदगी नहीं झेलनी पड़ेगी। तब फिर किसी दिन चारबाग स्टेशन पर उतरने वाला यात्री, आलमबाग बस अड्डे पर पहुंचने वाला मुसाफिर और चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर कदम रखने वाला आगंतुक जब उस संदेश को पढ़ेगा– 'मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं '–तो लखनऊ भी पूरी ईमानदारी और आत्मविश्वास के साथ मुस्कुरा सकेगा। क्योंकि तब उसके माथे पर लापरवाही का कलंक नहीं, बल्कि जागरूकता और जिम्मेदारी का प्रकाश होगा।

लखनऊ की पहचान केवल उसकी तहजीब, अदब और मेहमाननवाजी से नहीं है, बल्कि उस स्वागत भाव से भी है जो शहर में कदम रखते ही महसूस होने लगता है। चाहे चारबाग रेलवे स्टेशन हो, आलमबाग बस अड्डा हो या चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा–बाहर से आने वाले हर आगंतुक का स्वागत एक संदेश करता है, 'मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। '

लेकिन मंगलवार को ऐसा लगा जैसे स्वयं लखनऊ अपनी निगाहें झुकाए खड़ा हो। मानो उसमें इतनी हिम्मत ही न बची हो कि वह किसी आगंतुक से कह सके–मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। उसके पास मुस्कुराने की कोई वजह नहीं थी। उसकी आंखों में शर्म, दुःख और पश्चाताप था। कारण था वह भीषण अग्निकांड, जिसने 15 युवा जीवनों को हमसे छीन लिया। वे केवल आंकड़े नहीं थे। वे सपने थे। सभी की उम्र 18 से 30 वर्ष के बीच थी–वह उम्र जब इंसान भविष्य के सबसे सुंदर सपने देखता है।

सोमवार दोपहर लगभग डेढ़ बजे तक वे अपने-अपने काम में लगे थे। कुछ देर बाद भोजन करने की तैयारी थी। तभी सूचना मिली कि भवन में आग लग गई है। इसके बाद जो हुआ, वह किसी दुःस्वप्न से कम नहीं था। भवन का प्रवेश द्वार डिजिटल लॉक से नियंत्रित था। बिजली गुल हुई तो वह लॉक भी जाम हो गया। पूरी इमारत कांच से बंद थी। कहीं खिड़की नहीं, कहीं वैकल्पिक निकास नहीं। केवल एक सीढ़ी थी और दुर्भाग्य से आग उसी सीढ़ी वाले हिस्से में लगी थी। वह सीढ़ी निकास मार्ग नहीं, बल्कि धुएं और आग को ऊपर पहुंचाने वाली चिमनी बन गई।

ऊपरी मंजिलों पर धुआं भरता गया। लोगों को अग्निकांड जैसी स्थिति से निपटने का कोई प्रशिक्षण नहीं था। जो जहां से बच सकता था, उसने बचने की कोशिश की। कुछ लोगों ने शीशा तोड़ा और पाइप के सहारे नीचे उतरे। एक युवक दूसरी मंजिल से कूद गया। एक अन्य बिजली के तारों पर कूदकर नीचे पहुंचा। कई लोग घायल हुए, लेकिन जीवित बच गए। दुर्भाग्य से सभी इतने भाग्यशाली नहीं थे।

कुछ युवक स्टूडियो के भीतर ही रह गए। कुछ ने बाथरूम को सुरक्षित स्थान समझकर उसके भीतर शरण ली और दरवाजा बंद कर लिया। शायद उन्हें लगा होगा कि धुआं और आग वहां तक नहीं पहुंचेगी। लेकिन वही स्थान उनकी अंतिम शरणस्थली बन गया। दम घुटने से उनकी मृत्यु हो गई। जब अग्निशमन कर्मियों ने आग पर काबू पाने के बाद एक-एक कर शव बाहर निकाले तो वहां उपस्थित हर व्यक्ति की आंखें नम थीं। मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, पुलिसकर्मी, पत्रकार, आम नागरिक–कोई भी उस दृश्य से अछूता नहीं रह सका। उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की आंखें भर आईं। अनेक पत्रकारों की आवाजें रुक गईं। कैमरे चल रहे थे लेकिन कैमरे के पीछे खड़े लोगों के आंसू भी बह रहे थे।यह केवल एक हादसा नहीं था। यह हमारी सामूहिक विफलता का आईना था।

प्रश्न यह है कि क्या केवल भवन गिरा देने से न्याय हो जाएगा? क्या कुछ गिरफ्तारियां कर देने से भविष्य सुरक्षित हो जाएगा? क्या केवल जांच आयोग बना देने से अगली दुर्घटना रुक जाएगी?

उत्तर है–नहीं। क्योंकि यह समस्या केवल एक भवन की नहीं है। लखनऊ ही नहीं, देश के लगभग हर शहर में ऐसे सैकड़ों-हजारों

भवन मौजूद हैं जहां सुरक्षा मानकों की अनदेखी की जा रही है। कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी, कॉल सेंटर, रेस्टोरेंट, गोदाम, शोरूम, निजी कार्यालय–कई स्थान ऐसे हैं जहां अग्निशमन सुरक्षा केवल कागजों में मौजूद है।

लेकिन क्या केवल व्यवस्था दोषी है?

निस्संदेह प्रशासन की जिम्मेदारी सबसे बड़ी है। निरीक्षण करना, नियम लागू कराना, उल्लंघन पर कार्रवाई करना उसका कर्तव्य है। भवन मालिक और नियोक्ता भी सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। लेकिन इस पूरे विमर्श में एक पक्ष ऐसा है जिसकी चर्चा कम होती है–और वह है आम नागरिक, कर्मचारी, विद्यार्थी और उपभोक्ता।

जिस भवन में हम काम करते हैं, क्या हमने कभी पूछा कि वहां अग्निशमन यंत्र हैं या नहीं? जिस कोचिंग में हम पढ़ते हैं, क्या हमने देखा कि आपातकालीन निकास कहां है?

जिस स्कूल में हमारा बच्चा पढ़ता है, क्या हमने यह जानने की कोशिश की कि वहां सुरक्षा मानकों का पालन होता है या नहीं?

जिस बस में हम सफर करते हैं, क्या हमने देखा कि चालक प्रशिक्षित है या नहीं? जिस सीवर में मजदूर को उतारा जा रहा है, क्या हमने कभी पूछा कि उसके पास सुरक्षा उपकरण हैं या नहीं?

सच्चाई यह है कि अधिकांश मामलों में उत्तर 'नहीं' होगा।

हम व्यवस्था से अपेक्षा करते हैं कि वह सब कुछ देखे, लेकिन स्वयं देखने की जिम्मेदारी नहीं निभाते। जबकि सबसे पहले खतरा हमारे जीवन को है। किसी भी कार्यस्थल पर काम करने वाले कर्मचारी को यह अधिकार है कि वह सुरक्षित वातावरण की मांग करे। किसी छात्र को यह अधिकार है कि वह सुरक्षित शिक्षण संस्थान की अपेक्षा करे। किसी ग्राहक को यह अधिकार है कि वह सुरक्षित प्रतिष्ठान में ही जाए। यदि कहीं सुरक्षा मानकों का पालन नहीं हो रहा है तो उसकी सूचना संबंधित विभाग को देना भी नागरिक कर्तव्य है।

प्रतिस्पर्धा और रोजगार की मजबूरियां अपनी जगह हैं, लेकिन जीवन से बड़ा कुछ नहीं है।

हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमारा जीवन केवल हमारा नहीं है। हमारे माता-पिता, बच्चे, जीवनसाथी, भाई-बहन और परिवार की उम्मीदें उससे जुड़ी हैं। हमारा जीवन हमारे पास एक अमानत की तरह है। किसी भी नियोक्ता, संस्थान या भवन मालिक को यह अधिकार नहीं दिया जा सकता कि वह लापरवाही के कारण उस अमानत को खतरे में डाल दे। मंगलवार को लखनऊ का अंतिम बड़ा मंगल था। सामान्यतः इस दिन शहर उत्सव के रंग में डूबा रहता है। जगह-जगह भंडारे लगते हैं। लोग परिवार सहित निकलते हैं। सामाजिक मेल-मिलाप का वातावरण बनता है। लेकिन इस बार तस्वीर अलग थी। कई कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए। अनेक सार्वजनिक आयोजन रद्द हुए। जहां भंडारे लगे भी, वहां वह उत्साह नहीं दिखा जिसके लिए लखनऊ जाना जाता है। लोगों की बातचीत में केवल एक ही विषय था–वे 15 युवा जिनके घरों में अब कभी वैसी खुशियां नहीं लौटेंगी जैसी सोमवार सुबह थीं।

शहर शोक में था। शायद पहली बार लखनऊ को स्वयं अपने स्वागत संदेश से असहजता महसूस हो रही थी। लेकिन शोक का सबसे बड़ा उद्देश्य केवल दुःख मनाना नहीं होता। उसका उद्देश्य सीख लेना भी होता है। यदि इस हादसे के बाद भी हम नहीं चेते, यदि हम अब भी सुरक्षा को औपचारिकता समझते रहे, यदि कर्मचारी, विद्यार्थी, अभिभावक और नागरिक अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक नहीं हुए, तो यह त्रासदी व्यर्थ चली जाएगी।

हमें तय करना होगा कि हम ऐसे विद्यालयों में बच्चों को नहीं भेजेंगे जहां सुरक्षा मानक पूरे नहीं हैं। ऐसे कोचिंग संस्थानों में प्रवेश नहीं लेंगे जहां आपातकालीन निकास तक नहीं है। ऐसे प्रतिष्ठानों में काम नहीं करेंगे जहां कर्मचारियों की सुरक्षा की उपेक्षा होती है। ऐसे निर्माण कार्यों को अनदेखा नहीं करेंगे जहां मजदूरों को बिना सुरक्षा उपकरणों के जोखिम में डाला जा रहा है। जब नागरिक जागरूक होगा तभी व्यवस्था भी जवाबदेह बनेगी।

लखनऊ आज दुःखी है। शर्मिंदा भी है। लेकिन यदि यह पीड़ा समाज को जागरूक कर सके, यदि यह 15 युवाओं की असमय मृत्यु को एक बड़े सामाजिक परिवर्तन का कारण बना सके, तो शायद भविष्य में किसी और शहर को ऐसी शर्मिंदगी नहीं झेलनी पड़ेगी। तब फिर किसी दिन चारबाग स्टेशन पर उतरने वाला यात्री, आलमबाग बस अड्डे पर पहुंचने वाला मुसाफिर और चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर कदम रखने वाला आगंतुक जब उस संदेश को पढ़ेगा– 'मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं '–तो लखनऊ भी पूरी ईमानदारी और आत्मविश्वास के साथ मुस्कुरा सकेगा। क्योंकि तब उसके माथे पर लापरवाही का कलंक नहीं, बल्कि जागरूकता और जिम्मेदारी का प्रकाश होगा।

स्मार्टफोन संयमित उपयोग की वैश्विक जरूरत

ललित गर्ग

विज्ञान और तकनीक ने मानव सभ्यता को अभूतपूर्व गति प्रदान की है। आज का युग डिजिटल युग है, जहां एक क्लिक पर पूरी दुनिया हमारी हथेली में सिमट आई है। स्मार्टफोन ने संचार, शिक्षा, व्यापार, बैंकिंग, स्वास्थ्य, शासन और सामाजिक संबंधों को नई दिशा दी है। लेकिन हर तकनीकी क्रांति अपने साथ कुछ गंभीर चुनौतियां भी लेकर आती है। स्मार्टफोन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यह जितना बड़ा वरदान सिद्ध हुआ है, उतना ही बड़ा अभिशाप भी बनता जा रहा है। विशेष रूप से बच्चों और किशोरों पर इसके दुष्प्रभावों ने पूरी दुनिया को चिंतित कर दिया है। आज विश्वभर में यह स्वीकार किया जा रहा है कि स्मार्टफोन केवल एक उपकरण नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति है, जिसका विवेकपूर्ण उपयोग आवश्यक है। दुर्भाग्यवश, विवेक और अनुशासन के अभाव में इसका नकारात्मक पक्ष अधिक मुखर हो रहा है। स्मार्टफोन की लत बच्चों और युवाओं में मानसिक तनाव, अवसाद, एकाकीपन, हिंसक प्रवृत्तियों, अश्लीलता, साइबर अपराध और सामाजिक विघटन का कारण बन रही है। यही कारण है कि आज केवल परंपरागत समाज और विकासशील देश ही नहीं, बल्कि विकसित देश भी इस चुनौती से निपटने के लिए कठोर कदम उठा रहे हैं।

हाल ही में भारत के हरियाणा के नूंह जिले के सुखपुरी गांव की पहल ने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया। गांव की पहचान साइबर अपराध के केंद्र के रूप में बनने लगी थी। इससे आहत होकर ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से स्मार्टफोन त्यागने और बेसिक फोन अपनाने का निर्णय लिया। यह केवल मोबाइल तोड़ने की घटना नहीं, बल्कि समाज की उस पीड़ा की अभिव्यक्ति है, जो तकनीक के दुरुपयोग से उत्पन्न हुई है। गांव के युवाओं का विरोध भी स्वाभाविक है, क्योंकि आज शिक्षा, रोजगार, डिजिटल भुगतान और सरकारी सेवाएं स्मार्टफोन पर निर्भर हैं। इस घटना ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा किया है-क्या समाधान तकनीक का बहिष्कार है या उसके विवेकपूर्ण उपयोग का संस्कार? विश्व के अनेक देशों ने इस प्रश्न पर गंभीर चिंतन आरंभ कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ब्रिटेन, नीदरलैंड, चीन और अमेरिका जैसे देशों में बच्चों और किशोरों के स्मार्टफोन उपयोग को नियंत्रित करने की दिशा में अनेक पहलें हुई हैं। ऑस्ट्रेलिया ने किशोरों के सोशल मीडिया उपयोग पर आयु-सीमा तय करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। फ्रांस ने स्कूलों में स्मार्टफोन प्रतिबंध लागू किया है। ब्रिटेन में भी स्कूलों में मोबाइल उपयोग को सीमित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। अमेरिका में सोशल मीडिया कंपनियों के विरुद्ध मुकदमे दायर हुए हैं और उन पर भारी जुर्माने लगाए गए हैं। इन पहलों का उद्देश्य तकनीक का विरोध नहीं, बल्कि बच्चों के मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य की रक्षा करना है।

वास्तव में स्मार्टफोन जहां वरदान है, वहीं अभिशाप भी है। इससे ज्ञान का भंडार भी उपलब्ध है और भ्रम का संसार भी। यह शिक्षा का माध्यम भी है और अश्लीलता तथा हिंसा का प्रवेश-द्वार भी। यह रोजगार के अवसर भी देता है और साइबर अपराध की राह भी खोलता है। आज अनेक युवा रातों-रात अमीर बनने की लालसा में साइबर ठगी, सेक्सटॉर्शन, ऑनलाइन जुआ और डिजिटल धोखाधड़ी जैसे अपराधों में फंस रहे हैं। सोशल मीडिया पर फैल रही अश्लील सामग्री, फेक न्यूज, नफरत और ट्रोल संस्कृति ने सामाजिक मूल्यों को गहरी चोट पहुंचाई है। सबसे अधिक चिंता का विषय बच्चों और किशोरों का मानसिक स्वास्थ्य है। शोध बताते हैं कि अत्यधिक स्क्रीन टाइम से बच्चों की एकाग्रता, स्मरण शक्ति और रचनात्मक क्षमता प्रभावित होती है। नींद में कमी, चिड़चिड़ापन, अवसाद, चिंता, आत्महत्या की प्रवृत्ति और सामाजिक अलगाव जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। परिवारों में संवाद कम हुआ है और डिजिटल निकटता के बावजूद भावनात्मक दूरियां बढ़ी हैं। बच्चे खेल के मैदानों से दूर होकर आभासी दुनिया में खोते जा रहे हैं। विशेषतः 'स्मार्टफोन एक दुधारी तलवार है'। आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) और अत्याधुनिक संचार माध्यमों ने इस चुनौती को और अधिक जटिल बना दिया है। एआई जहां शिक्षा, चिकित्सा, अनुसंधान और प्रशासन के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला रही है, वहीं इसके दुरुपयोग की आशंकाएं भी तेजी से बढ़ रही हैं। डीपफेक वीडियो, फर्जी ऑडियो, साइबर ठगी, पहचान की चोरी, फेक न्यूज और डिजिटल ब्लैकमेल जैसे अपराधों में एआई का इस्तेमाल चिंताजनक स्तर तक बढ़ गया है। स्मार्टफोन इस पूरी प्रक्रिया का सबसे सुलभ और प्रभावी माध्यम बन गया है। एक साधारण मोबाइल फोन के माध्यम से आज कोई भी व्यक्ति एआई आधारित एप्लीकेशनों का उपयोग कर नकली तस्वीरें और वीडियो तैयार कर सकता है, भ्रामक सूचनाएं फैला सकता है या साइबर अपराधों को अंजाम दे सकता है। विशेष रूप से किशोर और युवा, जिनके पास तकनीकी कौशल तो है लेकिन नैतिक प्रशिक्षण और परिपक्वता का अभाव है, वे अनजाने में अथवा त्वरित लाभ की लालसा में ऐसे कृत्यों में संलिप्त हो सकते हैं। इसलिए आवश्यक है कि एआई और स्मार्टफोन के उपयोग के साथ-साथ डिजिटल नैतिकता, मानवीय मूल्यों और कानूनी जिम्मेदारियों का भी समुचित प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि तकनीक मानवता के विकास का साधन बने, विनाश का नहीं। इस संदर्भ में यह कथन अत्यंत प्रासंगिक है-'विज्ञान बिना विवेक के विनाश का कारण बनता है, जबकि विवेक के साथ वही विज्ञान मानवता का वरदान बन जाता है।' ऐसी स्थिति में भारत में भी व्यापक राष्ट्रीय विमर्श की आवश्यकता है।

ज्ञापन की राजनीति या जनशक्ति का हथियार? लोकतंत्र में ज्ञापनों का प्रभाव, सीमाएं और वास्तविकता

अनिल चौधरी

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहां प्रत्येक नागरिक को अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। लोकतंत्र की मूल भावना ही यह है कि जनता अपनी समस्याओं, मांगों और सुझावों को शासन-प्रशासन तक पहुंचाए और सरकार उन पर विचार करके आवश्यक निर्णय ले। इसी प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण माध्यम है–ज्ञापन **(Memorandum)**। देश में प्रतिदिन हजारों ज्ञापन विभिन्न संगठनों, किसान यूनियनों, कर्मचारी संघों, छात्र संगठनों, व्यापारिक संस्थाओं और आम नागरिकों द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों तथा जनप्रतिनिधियों को सौंपे जाते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि क्या इन ज्ञापनों का वास्तव में सरकार पर कोई प्रभाव पड़ता है? ज्ञापन देने के बाद कितनी मांगें स्वीकार होती हैं? क्या ज्ञापन देना केवल औपचारिकता बनकर रह गया है या यह आज भी जनहित के लिए एक प्रभावी लोकतांत्रिक हथियार है?

लोकतांत्रिक व्यवस्था में ज्ञापन को जनता और सरकार के बीच संवाद का सबसे शांतिपूर्ण और वैधानिक माध्यम माना जाता है। जब कोई व्यक्ति या संगठन किसी समस्या, अन्याय, नीति परिवर्तन या जनहित के मुद्दे को सरकार के सामने रखना चाहता है, तो वह लिखित रूप में अपनी मांगों और सुझावों को प्रस्तुत करता है। इसे ही ज्ञापन कहा जाता है। ज्ञापन देने का उद्देश्य केवल शिकायत करना नहीं होता, बल्कि सरकार का ध्यान किसी महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना भी होता है। भारतीय संविधान नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रखने का अधिकार देता है। इसी कारण ज्ञापन लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का अभिन्न हिस्सा बन गया है। चाहे किसानों की फसल का उचित मूल्य हो, कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने की मांग हो, छात्रों की परीक्षा संबंधी समस्याएं हों या किसी क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं का मुद्दा–हर विषय पर ज्ञापन दिए जाते हैं। यदि प्रभाव की बात करें तो ज्ञापन का असर पूरी तरह उसके विषय, जनसमर्थन, राजनीतिक परिस्थितियों और प्रशासनिक इच्छाशक्ति पर निर्भर करता है। कई बार एक छोटा-सा ज्ञापन भी सरकार को बड़ा निर्णय लेने के लिए मजबूर कर देता है, जबकि कई बार हजारों लोगों द्वारा दिए गए ज्ञापन वर्षों तक फाइलों में दबे रह जाते हैं।

ज्ञापन का सबसे बड़ा प्रभाव यह होता है कि वह किसी मुद्दे को सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा बना देता है। जब कोई मांग लिखित रूप में प्रशासन तक पहुंचती है तो संबंधित विभाग के पास उसका रिकॉर्ड तैयार हो जाता है। भविष्य में यदि उस विषय पर विवाद या आंदोलन होता है तो यह प्रमाण मौजूद रहता है कि संबंधित पक्ष ने पहले ही अपनी मांग या समस्या से सरकार को अवगत करा दिया था। इसके अलावा ज्ञापन मीडिया और जनमत को प्रभावित करने का भी माध्यम होता है। अक्सर देखा जाता है कि किसी संगठन द्वारा ज्ञापन देने के बाद मीडिया में उस विषय को प्रमुखता मिलती है, जिससे सरकार पर दबाव बढ़ता है। लोकतंत्र में जनमत का दबाव कई बार प्रशासनिक निर्णयों को प्रभावित करता है।

हालांकि वास्तविकता यह भी है कि देश में दिए जाने वाले अधिकांश ज्ञापनों पर तत्काल कार्रवाई नहीं होती। कई बार अधिकारी केवल ज्ञापन प्राप्त कर लेते हैं, आश्वासन दे देते हैं और मामला वहीं समाप्त हो जाता है। यही कारण है कि आम जनता के बीच यह धारणा बन गई है कि ज्ञापन देना केवल एक औपचारिकता रह गया है। लेकिन यह पूरी तरह सत्य नहीं है। यदि किसी ज्ञापन के पीछे मजबूत जनसमर्थन, तथ्यात्मक आधार और लगातार अनुवर्ती कार्रवाई **(Follow-up)** हो तो उसके सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। इतिहास गवाह है कि कई बड़े जनआंदोलनों की शुरुआत एक साधारण ज्ञापन से

ही हुई थी। बाद में वही आंदोलन सरकारों को नीतियां बदलने के लिए मजबूर कर गए। जहां तक मांगों के स्वीकार होने का प्रश्न है, इसका कोई निश्चित आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। फिर भी प्रशासनिक विशेषज्ञों का मानना है कि अधिकांश ज्ञापनों में उठाई गई सभी मांगें स्वीकार नहीं होतीं। कई बार कुछ मांगें मान ली जाती हैं, कुछ पर विचार किया जाता है और कुछ को अस्वीकार कर दिया जाता है। सरकार हर मांग को केवल इसलिए नहीं मान सकती क्योंकि उसे ज्ञापन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उसे आर्थिक संसाधनों, कानूनी बाधाओं, प्रशासनिक प्रक्रियाओं और व्यापक जनहित को भी ध्यान में रखना पड़ता है। उदाहरण के लिए यदि किसी क्षेत्र के लोग सड़क निर्माण की मांग करते हैं और बजट उपलब्ध है तो सरकार उस पर कार्यवाही कर सकती है। लेकिन यदि कोई मांग वर्तमान कानूनों या वित्तीय स्थिति के विपरीत है तो उसे स्वीकार करना कठिन हो जाता है। इसलिए ज्ञापन की सफलता केवल मांग की वैधता पर ही नहीं बल्कि उसकी व्यवहारिकता पर भी निर्भर करती है। ज्ञापन देने के कई लाभ हैं। सबसे पहला लाभ यह है कि यह लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग है। इससे नागरिकों को अपनी बात रखने का अवसर मिलता है। दूसरा लाभ यह है कि इससे समस्याएं सरकार के संज्ञान में आती हैं। कई बार प्रशासन को किसी क्षेत्र की वास्तविक समस्या की जानकारी ही नहीं होती। ज्ञापन उस कमी को दूर करता है। तीसरा लाभ यह है कि ज्ञापन संघर्ष का शांतिपूर्ण तरीका है। हिंसक प्रदर्शन, तोड़फोड़ और कानून व्यव-स्था बिगाड़ने की बजाय ज्ञापन लोकतांत्रिक मर्यादाओं के भीतर रहकर विरोध दर्ज कराने का माध्यम है। चौथा लाभ यह है कि इससे जनता के बीच जागरूकता बढ़ती है और लोग अपने अधिकारों के प्रति सजग होते हैं। पांचवां लाभ यह है कि ज्ञापन भविष्य के आंदोलनों की आधारशिला बन सकता है। यदि सरकार मांगों की अनदेखी करती है तो ज्ञापन यह साबित करता है कि जनता ने पहले शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने का प्रयास किया था। इससे आगे के लोकतांत्रिक आंदोलनों को नैतिक मजबूती मिलती है। लेकिन ज्ञापन देने की कुछ हानियां और सीमाएं भी हैं।

सबसे बड़ी समस्या यह है कि कई बार ज्ञापन केवल फोटो खिंचवाने और समाचारों में स्थान पाने का माध्यम बन जाते हैं। कुछ संगठन और नेता वास्तविक समाधान की बजाय केवल औपचारिक विरोध दर्ज कराकर अपनी सक्रियता दिखाने का प्रयास करते हैं। **दूसरी** समस्या यह है कि ज्ञापन देने के बाद अधिकांश लोग उसके परिणामों की निगरानी नहीं करते। एक बार ज्ञापन सौंपने के बाद मामला भूल जाते हैं। ऐसी स्थिति में प्रशासन पर कोई दबाव नहीं बनता और मांगें अधूरी रह जाती हैं। **तीसरी** हानि यह है कि बार-बार ज्ञापन देने के बावजूद जब कोई कार्रवाई नहीं होती तो जनता का लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से विश्वास कम होने लगता है। लोगों को लगने लगता है कि उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। **चौथी** समस्या यह है कि कई बार ज्ञापन अव्यावहारिक या राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित होते हैं। ऐसे ज्ञापनों का उद्देश्य समस्या का समाधान नहीं बल्कि राजनीतिक लाभ प्राप्त करना होता है। इससे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की गंभीरता प्रभावित होती है। अब प्रश्न उठता है कि क्या ज्ञापन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? इसका उत्तर स्पष्ट रूप से 'हाँ' है। ज्ञापन अवश्य देना चाहिए, लेकिन केवल औपचारिकता के लिए नहीं। ज्ञापन तथ्यात्मक, स्पष्ट और जनहित आधारित होना चाहिए। उसके साथ पर्याप्त प्रमाण और आंकड़े होने चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ज्ञापन देने के बाद उसकी निरंतर निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई भी होनी चाहिए।यदि किसी मांग को लेकर केवल ज्ञापन देकर चुप बैठ जाया जाए तो सफलता की संभावना कम हो जाती है। लेकिन यदि ज्ञापन के बाद जनप्रतिनिधियों से संपर्क, सूचना के अधिकार **(RTI)** का प्रयोग, मीडिया के माध्यम से मुद्दे को उठाना और आवश्यक होने पर शांतिपूर्ण जनआंदोलन किया जाए तो परिणाम मिलने की संभावना बढ़ जाती है। आज के डिजिटल युग में ज्ञापन का स्वरूप भी बदल रहा है। ऑनलाइन याचिकाएं, ई-मेल अभियान, सोशल मीडिया अभियानों और डिजिटल हस्ताक्षर अभियानों ने जनता को अपनी आवाज अधिक प्रभावी ढंग से उठाने का अवसर दिया है। सरकारें भी अब जनमत को पहले की तुलना में अधिक गंभीरता से लेने लगी हैं क्योंकि सूचना और संचार के आधुनिक साधनों ने जनता की आवाज को व्यापक बना दिया है।

अंततः कहा जा सकता है कि लोकतंत्र में ज्ञापन केवल कागज का एक टुकड़ा नहीं बल्कि जनता की सामूहिक इच्छा और अधिकारों की अभिव्यक्ति है। इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसे कितनी गंभीरता, तैयारी और निरंतरता के साथ प्रस्तुत किया गया है। ज्ञापन न तो पूरी तरह निष्प्रभावी है और न ही हर समस्या का समाधान। यह लोकतांत्रिक संघर्ष का पहला कदम है, अंतिम नहीं।

यदि जनता संगठित होकर तथ्य और तर्क के साथ अपनी मांग रखे तथा उसके लिए लगातार प्रयास करती रहे, तो ज्ञापन सरकार को निर्णय लेने के लिए मजबूर करने वाला प्रभावी हथियार बन सकता है। लेकिन यदि यह केवल औपचारिकता, फोटो अवसर या राजनीतिक दिखावे तक सीमित रह जाए, तो इसकी उपयोगिता बहुत कम हो जाती है।

भगवान झूलेलाल की पूजा-अर्चना

स्पीकर देवनानी ने प्रथम सिंधु कुंभ में की सिंधु नदी एवं भगवान झूलेलाल की पूजा-अर्चना

सिंधु कुंभ भारत की सांस्कृतिक एकात्मता का विराट उत्सव : वासुदेव देवनानी

देवनानी बोले-लद्दाख की अलौकिक प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक धरोहरों और राष्ट्रभावना से ओतप्रोत वातावरण इस आयोजन को विशेष बनाता है

जयपुर(नि.सं.)। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने लेह-लद्दाख में आयोजित प्रथम सिंधु कुंभ के अंतर्गत पवित्र सिंधु घाट पर मां सिंधु नदी एवं भगवान झूलेलाल जी की पूजा-अर्चना कर देश, प्रदेश एवं समाज की सुख-समृद्धि, शांति तथा प्रगति की कामना की। सिंधु नदी राष्ट्रीय अस्मिता की अमर प्रतीक - इस अवसर पर श्री देवनानी ने कहा कि सिंधु नदी केवल एक जलधारा नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता, संस्कृति और राष्ट्रीय अस्मिता की अमर प्रतीक है।

सिंधु के पावन तट पर श्रद्धा, संस्कृति और राष्ट्रीय एकता का जो अद्भुत संगम दिखाई देता है, वह भारत की सनातन परंपरा और सांस्कृतिक विरासत का सशक्त परिचायक है।

सिंधु दर्शन यात्रा प्रथम सिंधु कुंभ के रूप में एक नए अध्याय की साक्षी : श्री देवनानी ने कहा कि सिंधु दर्शन यात्रा अपने 30वें वर्ष में प्रथम सिंधु कुंभ के रूप में एक नए अध्याय की साक्षी बन रही है। 22 से 27 जून तक आयोजित इस महाआयोजन में धार्मिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय एकता से जुड़े विविध कार्यक्रमों के माध्यम से भारत की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत तथा सांस्कृतिक गौरव का भव्य प्रदर्शन हो रहा है।

लद्दाख की अलौकिक प्राकृतिक सुंदरता : देवनानी ने कहा कि लद्दाख की अलौकिक प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक धरोहरों और राष्ट्रभावना से ओतप्रोत वातावरण इस आयोजन को विशेष बनाता है। देश के विभिन्न भागों से आए श्रद्धालुओं, संत-महात्माओं और सामाजिक प्रतिनिधियों की सहभागिता राष्ट्रीय एकता के भाव को और अधिक सुदृढ़ कर रही है।

देवनानी की निर्जला एकादशी पर शुभकामनाएं: निर्जला एकादशी के पावन अवसर पर राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं एवं बधाई दी है। श्री देवनानी ने कहा कि निर्जला एकादशी भारतीय सनातन संस्कृति में श्रद्धा, संयम, तप एवं आत्मशुद्धि का महत्वपूर्ण पर्व है।

अन्नदाता के ऊर्जादाता बनने का संकल्प हुआ साकार

सोलर पैनलों के नीचे लहलहा रही फसल- ऊपर पैदा हो रही बिजली

कुंदनपुरा गांव में स्थापित हुआ देश का पहला एग्री पीवी प्लांट

जयपुर(नि.सं.)। जयपुर जिले के कुंदनपुरा गांव (बस्सी-तूंगा) गांव में पायलट प्रोजेक्ट की सफलता ने प्रधानमंत्री कुसुम योजना में स्थापित पारम्परिक सौर ऊर्जा संयंत्र से अलग हटकर अन्नदाता के साथ-साथ ऊर्जादाता होने का संकल्प साकार कर दिखाया है। दरअसल कुसुम योजना में अब तक जो सौर ऊर्जा पैनल लगते थे, उनके पीवी सेल स्ट्रक्चर की ऊंचाई जमीन से मात्र दो से तीन फीट होने के कारण उनके नीचे फसल ले पाना संभव नहीं होता था। किसान कुछ मात्रा में ही गिनी चुनी सब्जियों की खेती कर पाते थे। ऐसे में इंडियन काउन्सिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकॉनोमिक रिलेशंस (आईसीआरआईईआर) ने कोटक महिन्द्रा बैंक के वित्तीय सहयोग से कुंदनपुरा में पायलट प्रोजेक्ट के तहत किसान श्री कजोडमल जाट द्वारा पूर्व में स्थापित कुसुम प्लांट के सोलर पैनल की ऊंचाई बढ़ाकर उसे एग्री-पीवी प्लांट का स्वरूप प्रदान किया है। दरअसल एग्री पीवी प्लांट आधुनिक तकनीक है जिसमें सोलर पैनलों को 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर लगवाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि नीचे फसलों को बढवार के लिए आवश्यक धूप एवं रोशनी मिल सके और ट्रेक्टर आसानी से घूम सके। इसका सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि भूमि का बिजली उत्पादन के साथ साथ फसल उत्पादन में भी उपयोग संभव हो रहा है।

न्यूज इन बॉक्स

राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी ने डीडवाना-कुचामन की ग्राम पंचायत सोलाया में किया ग्रामीण सेवा शिविर का अवलोकन

जयपुर(नि.सं.)। राजस्व राज्य मंत्री श्री विजय सिंह चौधरी ने बुधवार को डीडवाना-कुचामन जिला के नावां उपखंड की ग्राम पंचायत सोलाया में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने शिविर में विभिन्न विभागों के कार्यों का अवलोकन किया और विभागों द्वारा किये जा रहे कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। राज्यमंत्री श्री चौधरी ने अधिकारियों को शिविरों में आमजन की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण सुनिश्चित कर अधिक से अधिक आमजन को लाभांवित करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर राज्य मंत्री श्री चौधरी ने पात्र लाभार्थियों को उनकी आवासीय भूमि के पट्टे वितरित किये तथा जनकल्याणकारी योजनाओं के स्वीकृति पत्र प्रदान किये। उन्होंने कहा कि सरकार का मुख्य ध्येय अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाना है, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा सेवा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने ग्रामीणों को शिविरों में भाग लेकर राज्य सरकार की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने का आह्वाहन भी किया।

राष्ट्रीय एकता शिविर के लिए जयपुर से रवाना हुआ राजस्थान का एनएसएस दल

जयपुर(नि.सं.)। राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के स्कूल स्तरीय राष्ट्रीय एकता शिविर में भाग लेने के लिए राजस्थान के स्वयंसेवकों के दल को बुधवार को शिक्षा संकुल स्थित कार्यालय से रवाना किया गया। यह राष्ट्रीय एकता शिविर हरियाणा सरकार द्वारा 24 जून से 30 जून 2026 तक महेंद्रगढ़ जिले के खातोद में आयोजित किया जा रहा है। शिविर का मुख्य विषय 'युवा फॉर माय भारत' एवं 'युवा फॉर डिजिटल लिटरेसी' रखा गया है, जिसके माध्यम से देशभर के युवाओं में राष्ट्रीय एकता, सामाजिक सहभागिता तथा डिजिटल साक्षरता के प्रति जागरूकता विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) जयपुर सुनील सिंघल ने बताया कि शिविर में देश के विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों से कुल 91 स्वयंसेवक भाग ले रहे हैं। इनमें 45 छात्र और 46 छात्राएं शामिल हैं।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री की उच्च स्तरीय बैठक

डेंगू, मलेरिया एवं अन्य संक्रामक रोगों से निपटने के लिए व्यापक तैयारियों के निर्देश

जयपुर(नि.सं.)। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने स्वास्थ्य भवन में प्रदेश में वर्षा ऋतु के दौरान संभावित मौसमी बीमारियों की रोकथाम, नियंत्रण एवं उपचार व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए विभागीय अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक ली। बैठक में डेंगू, मलेरिया, स्क्रब टाइफस, वायरल बुखार तथा जलजनित रोगों की स्थिति और उनसे निपटने के लिए की जा रही तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई। चिकित्सा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन को समय पर एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में किसी प्रकार की कमी नहीं रहे। उन्होंने अस्पतालों में पर्याप्त दवाइयों, जांच किटों, बेड, ऑक्सीजन, आवश्यक उपकरणों तथा चिकित्सकीय स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

खींवसर ने कहा कि संवेदनशील क्षेत्रों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए तथा रोगियों की शीघ्र पहचान एवं उपचार के लिए विशेष टीमों को सक्रिय रखा जाए। उन्होंने जिला स्तर पर कंट्रोल रूम को प्रभावी ढंग से संचालित करने तथा स्वास्थ्य संस्थानों में त्वरित प्रतिक्रिया व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने जयपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर एवं सवाई माधोपुर जिलों में डेंगू, प्रतापगढ़, सलूम्बर, बाड़मेर, उदयपुर एवं बांसवाड़ा जिलों में मलेरिया तथा कोटा, बूंदी, बारां, जयपुर व झालावाड़ जिलों में स्क्रब टाइफस मौसमी बीमारियों की विशेष निगरानी एवं व्यवस्थाओं पर आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में साफ-सफाई, फॉगिंग, एंटी-लार्वा गतिविधियों एवं पेयजल की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया गया। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि स्थानीय निकायों एवं संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर व्यापक स्तर पर जनजागरूकता अभियान चलाया जाए ताकि लोग अपने आसपास पानी जमा न होने दें और स्वच्छता बनाए रखें।

शहरी सेवा शिविर का अवलोकन

विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड अध्यक्ष ने हनुमानगढ़ जिले में शहरी सेवा शिविर का किया अवलोकन

जयपुर(नि.सं.)। विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड के अध्यक्ष (राज्यमंत्री दर्जा) रामगोपाल सुथार ने हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित दुर्गा मंदिर धर्मशाला में आयोजित शहरी सेवा शिविर का अवलोकन किया। उन्होंने विभिन्न विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण कर आमजन को उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं की जानकारी ली तथा अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश दिए कि राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचे और योजनाओं का लाभ समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराया जाए। सुथार ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। इस दौरान विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र एवं प्रमाण-पत्र वितरित किए गए। बड़ी संख्या में नागरिकों ने शिविर में भाग लेकर सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त किया।

जनता चुनाव जिताकर भेजती है,वे पैसे खाकर बिक जाते हैं:गहलोत

बोले- मैंने किसी का अपमान नहीं किया; कहा-यमुना जल आया तो सीएम को माला पहनाऊंगा

जोधपुर(वि.सं.)। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर एमएलए-एमपी के बिकने का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि जनता चुनाव जिताकर भेजती है और वे पैसे खाकर बिक रहे हैं। गहलोत ने यह भी कहा कि मैंने ऐसा कहकर किसी का अपमान नहीं किया। मैंने ऐसा दल बदलने वाले नेताओं के लिए कहा था। दरअसल, मंगलवार को भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ जोधपुर दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने अशोक गहलोत के दिए गधे-घोड़े और भैंस-बकरी की तरह बिक रहे एमएलए-एमपी के बयान पर पलटवार किया था।

सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा

फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति तक बैठे व्यक्ति तक पहुँचाना हमारा दायित्व : राजीव द्विवेदी

जयपुर(नि.सं.)। राजस्थान सरकार के 15 विभागों की 25 फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम राजीव द्विवेदी ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में की। उन्होंने कहा कि सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति तक बैठे व्यक्ति तक पहुँचाना हमारा दायित्व है। उन्होंने जिला रसद अधिकारी प्रथम प्रियव्रत सिंह चारण को निर्देशित किया कि वे पात्र नवीन परिवारों को एनएफएसए से लाभान्वित करने हेतु ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविरों में उपखण्ड अधिकारी व विकास अधिकारी कार्यालयों में लंबित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण करवाया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों का त्वरित निस्तारण करने के निर्देश संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिए। अतिरिक्त जिला कलक्टर ने कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में मिले 125 लक्ष्य के विरूद्ध 776 जल संरचनाओं का निर्माण करने पर प्रसन्नता व्यक्त करी। वहीं लखपति दीदी योजना में 95 प्रतिशत उपलब्धि अर्जित करने पर उन्होंने विभागीय अधिकारी को शीघ्र शत-प्रतिशत लक्ष्य अर्जित करने के लिए कहा। वहीं उन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता को अटल प्रगति पथ योजना के तहत आवंटित लक्ष्यों को शीघ्र पूर्ण करने के लक्ष्य भी प्रदान किए हैं। उन्होंने इस दौरान अन्य सभी विभागीय अधिकारियों को ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविरों में उपस्थित रहकर उनके विभाग से संबंधित फ्लैगशिप योजनाओं में यथासंभव लंबित कार्य पूर्ण कराकर प्रगति लाने के निर्देश प्रदान किए हैं। उन्होंने इस दौरान कुसुम योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण एवं शहरी, सहित अन्य फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा कर आवश्यक प्रगति लाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।

शारदा

बीकानेर में प्रसूता की मौत के चौथे दिन होगा पोस्टमॉर्टम

समझौता हुआ; 25 लाख रुपए भामाशाह देंगे, 50 लाख के प्रस्ताव सरकार को भेजेंगे

बीकानेर(वि.सं.)। बीकानेर के पीबीएम हॉस्पिटल में प्रसव के दौरान प्रसूता शारदा नायक की मौत होने के चौथे दिन परिजन और प्रशासन में सहमति बनी है। इसके बाद परिजनों की ओर से चल रहा धरना बुधवार को समाप्त हो गया। प्रशासन की ओर से आर्थिक सहायता और अन्य मांगों पर आश्वासन दिए जाने के बाद दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया। हालांकि अभी तक प्रशासन की ओर से कोई लिखित समझौता जारी नहीं किया गया है।

कांग्रेस देहात अध्यक्ष बिशनाराम सियाग ने बताया- एसडीएम राजेश नायक के साथ हुई बातचीत में प्रशासन ने जन सहयोग से 25 लाख रुपए की तत्काल सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है।

दलाल गिरफ्तार

फर्जी बीपीएड डिग्री दिलाने वाला दलाल गिरफ्तार

जयपुर(नि.सं.)। राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा-2022 में फर्जी बीपीएड डिग्री के जरिए नौकरी दिलाने के मामले में एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए वांछित दलाल पंकज कुमार जैन को गिरफ्तार किया है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, एसओजी, विशाल बंसल ने बताया कि एसओजी ने कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा-2022 में उत्तर प्रदेश के जे. एस. विश्वविद्यालय, शिकोहाबाद से फर्जी बीपीएड डिग्री जारी करने के मामले का खुलासा किया था। इस संबंध में 27 नवंबर 2024 को धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक षड्यंत्र सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। जांच में सामने आया कि दलाल पंकज जैन ने अपने सहयोगी पवन सिंह चौहान उर्फ पी.एस. चौहान के साथ मिलकर भर्ती अभ्यर्थी राजेश कुमार फागणा को फर्जी बीपीएड मार्कशीट उपलब्ध कराने का सौदा 1 लाख 30 हजार रुपए में किया था।

सरकार का वादा

किसान की आय बढ़ाने का सरकार का वादा

झारौटी के किसान भीमसिंह को हुआ 1.25 लाख का फायदा,मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को दिया धन्यवाद

जयपुर (नि.सं.)। केन्द्र और राज्य सरकार ने किसान की आय बढ़ाने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि, सिंचाई सुविधाओं के विकास और उन्नत बीज जैसी कई पहल की हैं। इसी क्रम में किसानों को उन्नत खेती के लिए कृषि उपकरण खरीदने के लिए अनुदान भी दिया जा रहा है। भरतपुर जिले के भुसावर में ग्राम पंचायत झारौटी निवासी भीमसिंह मीणा पुत्र रामजीवन मीणा को मल्टीक्रॉप थ्रेशर मशीन खरीदनी थी लेकिन वह इसकी कीमत 2.5 लाख रुपये चुकाने की स्थिति में नहीं था। उसने कृषि विभाग के अधिकारियों से बात की तो पता चला कि 2.5 लाख रु. देने की जरूरत नहीं है, आधा पैसा सरकार दे देगी। उसने फॉर्म भर दिया और मंगलवार को झारौटी में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर ने उसे 1 लाख 25 हजार रूपये का अनुदान स्वीकृत कर दिया गया। भीमसिंह के लिए खेती अब अधिक आधुनिक, लाभकारी और सुविधाजनक बन जायेगी, उत्पादन में वृद्धि होगी, आय बढ़ेगी। यह मशीन बीज और भूसे को अलग करने का कार्य तेजी और दक्षता से करती है, जिससे श्रम की आवश्यकता कम होती है और समय की बचत होती है। भीमसिंह ने बताया कि मल्टीक्रॉप थ्रेशर के प्रयोग से फसल की गुणवत्ता और चमक बनी रहती है, जिससे बाजार में उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त होता है। यह अनुदान केवल आर्थिक सहायता नहीं बल्कि आधुनिक कृषि की ओर बढ़ने का एक मजबूत आधार है।

डॉ किरोड़ीलाल मीणा पर सियासी हमला

गहलोत के पैरों में गिरकर रोए थे किरोड़ीः डोटासरा

बेनीवाल को चैलेंज किया था लेकिन 10 मिनट में सरेंडर, किरोड़ी के 1200 छापों की जांच हो

जयपुर(नि.सं.)। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कृषि मंत्री डॉ किरोड़ीलाल मीणा पर सियासी हमला बोलते हुए तत्कालीन सीएम अशोक गहलोत के पैरों में गिरकर गिडगिड़ाने के आरोप लगाए हैं। डोटासरा ने किरोड़ी पर खाद, बीज छापों में सैकड़ों करोड़ की अवैध वसूली के आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री से जांच की मांग की है। किरोड़ी ने डोटासरा के बेटे-बहू पर गलत तरीके से ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाकर आरएएस बनाने के आरोप लगाते हुए जांच के लिए सीएम को चिट्ठी लिखी। इस पर डोटासरा ने अब तल्ख पलटवार किया है। डोटासरा ने कहा- आज मैं सार्वजनिक रूप से कह रहा हूं, मुझे किरोड़ी ने एक बार कहा था कि मुख्यमंत्री से अलग से बात करनी है। मिलकर जब 15 मिनट बाद अशोक गहलोत निकले तो कहा कि इसे क्यों लाए थे मेरे पास? मैंने पूछा कि क्या हो गया? गहलोत बोले कि यह पैरों में बैठ गया कि मेरे खिलाफ मुकदमे हटा दीजिए। वो आदमी जो अशोक गहलोत के पैरों में पड़कर रोने लग गया था कि मेरे मुकदमे हटा लो, वह आदमी आज हम पर आरोप लगा रहा है, उसे शर्म आनी चाहिए। डोटासरा प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत के बाद जयपुर शहर कांग्रेस के कार्यक्रम में बोल रहे थे। डोटासरा ने कहा- किसी को इतना मत छेड़ो कि तुम्हारा बुढ़ापा खराब हो जाए। किरोड़ी ने एक दिन हनुमान बेनीवाल को चैलेंज किया था, 10 मिनट में ही सरेंडर हो गए, भ्या बोल गई किरोड़ीजी की।

4 जुलाई को पीएम करेंगे जयपुर मेट्रो फेज-2 का शिलान्यास

सांगानेर में 631 करोड़ के होंगे विकास कार्य, ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत

जयपुर(नि.सं.)। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेशभर में बिजली, पानी और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के साथ नागरिक सेवाओं को बेहतर बनाने पर प्राथमिकता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जयपुर में परिवहन

व्यवस्था से लेकर सफाई तंत्र तक को हाईटेक बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे भविष्य की जरूरतों को पूरा किया जा सके। बुधवार को सांगानेर में नगर निगम द्वारा आयोजित पट्टा वितरण एवं लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने यह बात कही। इस दौरान उन्होंने लगभग 631 करोड़ रुपए की लागत से 1538 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि इन कार्यों से क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी और अन्य मूलभूत सुविधाओं का विस्तार होगा तथा आमजन को बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी।

13 हजार करोड़ से अधिक की लागत से बनेगी जयपुर मेट्रो फेज-2

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई को जयपुर मेट्रो फेज-2 परियोजना का शिलान्यास करेंगे। उन्होंने बताया कि 13 हजार करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली इस परियोजना के तहत प्रहलादपुरा से पिंजरापोल गौशाला तक मेट्रो लाइन विकसित की जाएगी और इसके कार्यादेश भी जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह परियोजना राजधानी में यातायात को अधिक सुगम बनाने, यात्रा समय कम करने और शहरी विकास को नई गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में ऐसी कई योजनाएं शुरू हुई हैं, जिन्होंने शहरों को विकास का इंजन बनाया है।

हीटवेव की चपेट में 26 यूरोपीय देश

फ्रांस में गर्मी से 58 लोगों की मौतःन्यूक्लियर पावर प्लांट बंद करना पड़ा

पेरिस, लंदन(एजेंसी)। फ्रांस में गर्मी के कारण 58 लोगों की मौत हो गई। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक लोग गर्मी से राहत पाने के लिए नदियों, झीलों और नहरों में नहाने जा रहे हैं। इसके चलते पिछले कुछ दिनों में 40 लोगों की डूबकर मौत हो गई है। इनमें ज्यादातर युवा शामिल हैं। इसके साथ ही, 2 बच्चों समेत 18 लोगों की गर्मी में लू के चलते मौत हो गई। हीटवेव के चलते फ्रांस में गोलफेश न्यूक्लियर पावर प्लांट को सोमवार रात बंद करना पड़ा। इसकी वजह यह है कि प्लांट को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल होने वाली गारोन नदी का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की आशंका है। फ्रांस ही नहीं यूरोप के 26 देश हीटवेव की चपेट में हैं। स्पेन, इटली और ब्रिटेन समेत 14 देशों में गर्मी को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। इनमें से ज्यादातर देशों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर पहुंचने के करीब है।

फ्रांस में पब्लिक में शराब पीने पर रोक लगी

फ्रांस में सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने पर पाबंदी लगा दी है। मौसम एजेंसी ने बताया कि सोमवार रात देश ने 1947 में रिकॉर्ड शुरू होने के बाद की सबसे गर्म रात दर्ज की। कई हिस्सों में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। भीषण गर्मी के कारण 1,350 से ज्यादा स्कूल बंद कर दिए गए हैं।

न्यूज़ ब्रीफ

एअर इंडिया का विमान पाक एयरस्पेस में घुसा

दिल्ली से अमृतसर के लिए उड़ा, तकनीकी खराबी से रास्ता भटका, पाकिस्तान ने चेतावनी देकर लौटाया

अमृतसर(एजेंसी)। एअर इंडिया की एक फ्लाइट सोमवार रात रास्ता भटककर पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में जा घुसी। इसे पाकिस्तान की एयर ट्रैफिक अथॉरिटी ने चेतावनी देकर वापस भेजा। विमान ने दिल्ली से उड़ान भरी थी और इसे अमृतसर लैंड होना था। पाकिस्तान के एयर स्पेस से जब फ्लाइट लौटी तब तक अमृतसर एयरपोर्ट पर ट्रैफिक बढ़ गया था, ऐसे में इसे वापस दिल्ली भेज दिया गया। एयरपोर्ट अधिकारियों ने बताया है कि तकनीकी खराबी के कारण यह फ्लाइट रास्ता भटक गई थी। मामले की जांच की जा रही है। इससे पहले 12 जून को पाकिस्तान की भी पैसेंजर फ्लाइट फ्लाई जिन्ना-9P514 खराब मौसम के कारण भारतीय एयरस्पेस में घुस आई थी।

24 जून से 1 जुलाई तक आंगनबाड़ी केंद्रों पर खिलौना बैंक, प्रवेशोत्सव एवं पौधारोपण कार्यक्रम

जयपुर(नि.सं.)। आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3-6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शाला पूर्व शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 24 जून से 1 जुलाई तक विशेष अभियान चलाया जा है। समेकित बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस) निदेशक वासुदेव मालावत ने बताया कि बुधवार से आरम्भ इस अभियान के तहत सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर खिलौना बैंक की स्थापना के साथ प्रवेशोत्सव एवं पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आईसीडीएस निदेशक ने बताया कि जनसहभागिता से खिलौने जुटाकर बच्चों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देना तथा आंगनबाड़ी केंद्रों में नामांकन वृद्धि करने के लिए 24 से 30 जून तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका अपने क्षेत्र में गृह संपर्क कर समुदाय को खिलौना बैंक और नामांकन की जानकारी देंगी।

राज्यपाल से राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष की शिष्टाचार भेंट

जयपुर। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागडे से बुधवार को राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह ने लोकभवन पहुंचकर मुलाकात की। राज्यपाल श्री बागडे से उनकी यह शिष्टाचार भेंट थी।

राजस्थान फाउंडेशन चैप्टर्स एवं प्रवासी राजस्थानी संगठनों के साथ वर्चुअल संवाद

देश-विदेश से 200 से अधिक प्रवासी हुए शामिल, प्रदेश में निवेश संभावनाओं और भूमि आवंटन प्रक्रिया की दी गई जानकारी

जयपुर(नि.सं.)। राजस्थान फाउंडेशन, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी कार्य विभाग द्वारा प्रवासी राजस्थानी समुदाय के साथ नियमित संवाद एवं समन्वय करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की कड़ी में रीको, उद्योग भवन में वर्चुअल संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में देश-विदेश के राजस्थान फाउंडेशन चैप्टर्स और प्रवासी राजस्थानी संगठनों के प्रतिनिधि एवं निवेशकों सहित 200 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए। बैठक की शुरुआत राजस्थान फाउंडेशन के देश-विदेश में नव गठित 14 चैप्टर्स के माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान द्वारा मनोनीत अध्यक्षों को बधाई एवं शुभकामनाएँ देकर की गई। इस दौरान रीको के अधिकारियों ने राजस्थान में निवेश की संभावनाओं और भूमि आवंटन प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र (जेपीएमआईए),राजस्थान पेट्रो जोन में विकास एवं निवेश की संभावनाओं, भूमि लागत वसूली से संबंधित प्रावधानों , 'प्लग एंड प्ले' मॉडल के तहत उपलब्ध अवसरों तथा राज निवेश पोर्टल÷ का विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया गया। साथ ही, प्रतिभागियों द्वारा पूछे गए सवालों का रीको, उद्योग विभाग, बी आई पी के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा विस्तार से उत्तर दिया गया। राजस्थान फाउंडेशन की आयुक्त डॉ. मनीषा अरोड़ा ने बताया कि प्रवासी राजस्थानियों से संवाद के लिए नियमित वर्चुअल बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। देश-विदेश में बसे प्रवासियों में भी राज्य में निवेश की संभावनाओं को तलाशने एवं अपने व्यवसाय का विस्तार अपने राज्य में करने की प्रबल इच्छा ज़ाहिर होती है।

ट्रम्प ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की

ट्रम्प बोले-ईरान ने पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति को इज्जत दीः ईरान बोला- इस्लामाबाद समझौता अमेरिका की हार

तेल अवीव/ तेहरान/ वॉशिंगटन(एजेंसी)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दावा किया कि कई दशकों में पहली बार ईरान अमेरिका और उसके राष्ट्रपति को इतनी इज्जत दे रहा है। उन्होंने कहा कि ईरान इस समय कमजोर स्थिति में है और समझौते के लिए लगभग हर शर्त मानने को तैयार है। दूसरी ओर, ईरान के संसद अध्यक्ष बाघेर गालिबाफ ने कहा कि अमेरिका के साथ हुआ 'इस्लामाबाद समझौता' आखिरकार अमेरिका की हार बन चुका है। अजरबैजान में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने दावा किया कि यह समझौता किसी दबाव या मजबूरी का नतीजा नहीं था, बल्कि हमने इसे अपनी शर्तों पर माना है।

ईरान में 4 जुलाई से शुरू होगा खामेनेई का अंतिम संस्कार

ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के अंतिम संस्कार समारोह 4 जुलाई से शुरू होगा। अंतिम संस्कार समिति के प्रवक्ता ने कहा कि इससे जुड़ी तैयारियां कई बार पूरी कर ली गई थीं, लेकिन युद्ध की वजह से समारोह को बार-बार स्थगित करना पड़ा। उन्होंने बताया कि 8 जुलाई को इराक के पवित्र शहरों नजफ और करबला में भी अलग श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किए जाएंगे। ईरान और पूरे शिया मुस्लिम समुदाय में खामेनेई का बड़ा धार्मिक और राजनीतिक प्रभाव माना जाता है।

शादी से मना किया तो हनीमून की डीपफेक तस्वीरें बनाई

एक दिन में 500 टैक्सी घर भेजीं; गोद भराई के फर्जी कार्ड बंटवा दिए

भोपाल(एजेंसी)। एमपी की युवती का राजस्थान के युवक से शादी का इनकार पूरे परिवार के लिए मुसीबत बन गया। युवक ने उसके नाम-पते पर एक दिन में 500 टैक्सियां बुक कर दीं। टैक्सी वाले लड़की के घर पहुंचे और उससे टूर पर जाने का कहने लगे। युवती के उत्पीड़न का ये सिलसिला यहीं नहीं थमा। युवक ने AI से अपने साथ हनीमून, निजी पलों और गोदभराई के फोटो बनाकर फर्जी आईडी से पोस्ट कर दिए। इनका स्टेटस लगाया। युवती ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। फिर राज्य महिला आयोग से न्याय की गुहार लगाई। मामले की शुरुआत मेट्रिमोनियल साइट जीवनसाथी डॉट कॉम से होती है, जहां भोपाल युवती की बहन ने प्रोफाइल बनाई।

सिंधु नदी का पानी न मिलने से पाकिस्तान परेशान

इस्लामाबाद (एजेंसी)। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु नदी का पानी रोका, तो पाकिस्तान की परेशानियां बढ़ गई हैं। पाकिस्तान ने यह मसला अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में भी लेकिन वहां भी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ। इसके बाद अब रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भारत को जंग छेड़ने की धमकी दे रहे हैं। वहीं, आर्मी चीफ आसिम मुनीर जंग की साजिश रचने में जुटे हैं। नियंत्रण रेखा यानी रूष्ट पर पाकिस्तानी सेना की 8 ब्रिगेड ने 35 एंटी ड्रोन यूनिट तैनात की हैं। पाकिस्तान ने हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और काउंटर ड्रोन ग्रिड भी तैयार किया है। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से जुड़ी अपनी सीमाओं से 5 बटालियन को इस महीने की शुरुआत में ही मूव कराकर एलओसी के रावलाकोट, कोटली और भीम्बर सेक्टर में तैनात किया है।

पीएम सिंचाई योजना के प्रोजेक्ट में देरी से केंद्र नाराजःकेंद्रीय भूमि संसाधन विभाग एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सीएस को लिखा लेटर

जयपुर(नि.सं.)। केंद्र सरकार की योजना के काम में हो रही देरी पर केंद्रीय भूमि संसाधन विभाग एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्य सरकार पर नाराजगी जताई है। मंत्रालय ने पिछले दिनों एक पत्र मुख्य सचिव को लिखा है, जिसमें वाटरशेड विकास घटक-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (WDC-PMKSY 2.0) के तहत राजस्थान में चल रही परियोजनाओं की प्रगति का जिक्र किया है। मंत्रालय ने पत्र में कहा- साल 2021-22 में WDC-PMKSY 2.0 के तहत राजस्थान के लिए 8.05 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने वाली 159 वाटरशेड परियोजनाएं स्वीकृत की थी, जिनको पूरा करने के लिए मार्च 2026 तक का समय दिया था।

लेकिन समय पर काम पूरा नहीं हुआ। केंद्र सरकार ने वाटरशेड विकास कार्यों को पूरा करने के महत्व को देखते हुए इसे अस्थायी रूप से सितंबर 2026 तक बढ़ाने की अनुमति दी है। लेकिन काम में हो रही देरी और कार्य प्रगति अब भी संतोषजनक नहीं है। आपको बता दें कि इन परियोजनाओं की कुल लागत 1990.36 करोड़ रुपए थी, जिसमें केंद्र सरकार का हिस्सा 1194.22 करोड़ रुपए निर्धारित था।

राजस्थान संपर्क पोर्टल का निरीक्षण | **आरएमएससीएल के प्रबन्ध निदेशक ने किया राजस्थान संपर्क पोर्टल का निरीक्षण**

दवा संबंधी शिकायतों के त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश

जयपुर(नि.सं.)। राजस्थान चिकित्सा सेवाएं निगम लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक श्री पुखराज सेन ने राजस्थान संपर्क पोर्टल (181) के कॉल सेंटर का निरीक्षण कर मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना से संबंधित प्राप्त परिवादों एवं उनके निस्तारण की स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने परिवादियों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली तथा अधिकारियों को शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान श्री सेन ने विशेष रूप से ऐसे प्रकरणों की समीक्षा की जिनमें विभागीय कार्रवाई करने के बावजूद परिवादी समाधान से पूर्णतः संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने कहा

कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी जनकल्याणकारी योजना है और इससे सम्बंधित प्रत्येक परिवाद का संवेदनशीलता एवं गंभीरता के साथ निस्तारण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि दवा उपलब्धता, आपूर्ति एवं वितरण से संबंधित शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाए तथा संबंधित स्वास्थ्य संस्थानों और अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर उनका शीघ्र समाधान किया जाए ताकि आमजन को बेहतर व समय पर स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध हो सके। प्रबन्ध निदेशक ने संपर्क पोर्टल के कॉल सेंटर से कोटपुतली-बहरोड़ के विनोद, हनुमानगढ़ के आजाद, जोधपुर के मोहम्मद उस्मान, ब्यावर के आदम, भरतपुर के महेन्द्र सहित विभिन्न जिलों के परिवादियों से बात कर दवा प्राप्ति में आई समस्याओं की जानकारी ली। उन्होंने परिवादियों को आश्वस्त किया कि उनकी शिकायतों पर प्राथमिकता से कार्यवाही कर समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान संपर्क पोर्टल आमजन और सरकार के बीच प्रभावी संवाद का सशक्त माध्यम है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार आमजन की शिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण के लिए विभिन्न विभागों के सचिव निर्धारित तिथियों पर राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन (181) कंट्रोल रूम में उपस्थित होकर परिवादियों से सीधे संवाद कर रहे हैं।

इस पहल के माध्यम से आमजन घर बैठे अपनी शिकायत दर्ज कराकर उनके शीघ्र समाधान का लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक संपादकः नीरज मेहरा द्वारा बोनस ग्राफिक्स, लक्ष्मी नगर, झोटवाड़ा मार्ग, अजमेर रोड़, जयपुर-302006 से मुद्रित एवं 141, दयानन्द नगर, फेज प्रथम झालाना डूंगरी गली नंबर 19, थाना गांधी नगर, जयपुर (राज.) से प्रकाशित। प्रबंध संपादक- पी.के.बृजवाल, 9950325930, 9571635930 (कानूनी सलाहकार एडवोकेट कैलाशनाथ भट्ट)